

took place in the Con naught Circus, New Delhi branch of the bank in which two overdrafts were sanctioned against security of 'Kisaa Vikas Patras' which were subsequently found to be fake. The CBI have registered a case on 27.8.1998 against three persons involved in the fraud in which loans were availed against 'Kisan Vikas Patras' which were later found to be out of a lot of 'Kisan Vikas Patras' found missing from a railway parcel during transit from Nasik Press to Calcutta. Some arrests have been made. The bank has called for the explanation of the concerned staff and has also issued notices to all its branches/controlling authorities to exercise caution while financing against security of 'Kisan Vikas Patras'.

“इंडियन बैंक्स एमंग टैन मोस्ट करट” शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2519. श्री बरजिंदर सिंह:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 नवम्बर, 1998 के “दिविजनेस स्टैडर्ड” समाचार –पत्र में “इंडियन बैंक्स एमंग टैन मोस्ट करट: मोदीज” शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने भारतीय बैंकों के संबंध में अपनी राय प्रकट की है

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बर एम. आर. जनार्दन): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) यह समाचार मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर, 1998 को एक सम्मेलन में दिए गए “इम्प्रूविंग ट्रांसपैरेन्सी इन एशियन बैंकिंग सिस्टम नामक पत्र पर आधारित है। इस पत्र में घटिया पारदर्शिता की भूमिका का पूर्व एशियाई वित्तिय संकट पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण किया गया है। पत्र में

बताया गया है कि चूंकि पारदर्शिता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है तथा इसकी अवधारणा स्वयं में ही कुछ कुछ विषयप्रक रहती है, इसलिए पारदर्शिता के मातात्मक उपाय तैयार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सर्वेक्षण के परिणाम पर एजेंसी द्वारा भरोसा दिलाया गया है जिसमें कई देशों में भ्रष्टाचार की ज्ञात स्तर की मात्रा बताने का प्रयास किया गया है। ये सर्वेक्षण गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया गया है। प्रत्येक देश की 1 से 10 तक रैंकिंग केवल सर्वेक्षणों में भाग लेने वाले व्यावसाइयों की उपलब्धि के आधार पर ही की गई है। किसी देश को तभी भ्रष्टाचार सूची में शामिल किया जा सकता है जब कम से कम चार कारक हो। एजेंसी के अनुसार, कथित रूप से यह सूची, विभिन्न देशों की बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता का उपाय है। पत्र में उल्लिखित एशियाई बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता सुधार में कई एशियाई देशों समेत कुछ और देशों को भी संदर्भित किया गया गौ। परन्तु इसमें न तो विशेष रूप से भारत का उल्लेख किया गया है और न ही भारतीय बैंकों का। भारत का उल्लेख केवल परिशिष्ट में है जिसमें 52 देशों की सूची है और उन देशों में ज्ञात भ्रष्टाचार के स्तर को दर्शाता है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार, बैंकों के लेखों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सतत आधार पर कार्रवाई करते रहे हैं। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में कई उपाय किए गए हैं जिससे बैंकों के प्रकटीकरण में पहली की अपेक्षाओं वृद्धि हई है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण के लिए उद्देश्यप्रक मानदंडों के दृढ़ता से लागू किए जाने के कारण बैंकों के परिचालनों और लेखों में अधिक पारदर्शिता आई है।

आर्थिक स्थिती पर विचार करने हेतु परिषदों का गठन किया जाना

2520. श्री राज मोहिन्दर सिंह:

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत माहों के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करने एवं इस संबंध में सुझाव देने के लिए दों परिषदों का गठन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दोनों परिषदों को अलग-अलग दायित्व भी सौंपे गये थे ;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन परिषदों ने अब तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; यदि हाँ, तो तत्संबंधि व्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (घ) 27 अगस्त, 1998 और 28 अगस्त, 1998 को सरकार ने प्रधानमंत्री की “आर्थिक सलाहकार परिषद” और “व्यापार तथा उद्योग परिषद” नामक दो परिषदों का गठन किया जिनकी संरचना निम्नलिखि है:

आर्थिक सलाहकार परिषद

अध्यक्ष : प्रधानमंत्री
सदस्य : डा. आई. जी. पटेल
प्रो. पी. एन. धर
डा. मेटिक सिंह आहलुवालिया
डा. अर्जुन सेनगुप्ता
डा. किरिट पारिख
डा. अमरेश बागची
डा. अशोक देसाई

श्री जी. टी. रामाकृष्ण प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव सदस्य सचिव: प्रधानमंत्री के सचिव

व्यापार और उद्योग परिषद

अध्यक्ष: प्रधान मंत्री
सदस्य: श्री रतन टाटा
श्री मुकेश अम्बानी
श्री आर. पी. गोयनका
श्री पी. के. मितल
श्री कुमार मंगलम बिड़ला
श्री सुरेश कृष्णाओ (टी. वी. एस. समूह)
श्री एन. आर. नारायणमूर्ति (सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ)
श्री नुरली वाडिया
श्री ए. सी. मुरैया
डा. परविन्दर सिंह (उत्तर भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधि)
प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव

आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री और परिषद के सदस्यों के बीच अंतिमहत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर नीतीगत विचार-विमर्श के लिए एक अवसर प्रदान करेगी। इसी प्रकार, व्यापार और उद्योग परिषद प्रधानमंत्री और व्यापार था उद्योग परिषद के सदस्यों के बीच व्यापार और उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत

विचार-विमर्श के लिए एक अवसर प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग संबंधी सलाहकार परिषद के तहत छह विशेष संबंधी समूह गठित किए गए हैं। इन विशेष संबंधी समूहों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिन पर आगे की कार्रवाही के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एवं आजमगढ़ जनपदों में बैंकों की शाखाएं

2521. श्री मुनखर हसन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एवं आजमगढ़ जनपदों में कार्यरत विभीन्न बैंकों की शाखाओं का व्यौरा क्या है; और

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान दोनों जनपदों में मैम किन-किन बैंकों की शाखाएं खोली जाएंगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा भेजे गए अनुसार, 30 सितम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ जिलों में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का बैंक-वार विवरण संलग्न है। (उत्तर देखिए)

(ख) मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ जिलों में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निम्नलिखित प्राधिकार-पत्र जारी किए हैं:—

जिला	बैंक	केन्द्र
मुजफ्फरनगर	यूनियन बैंक	मुजफ्फरनगर
	आफ इंडिया	
मुजफ्फरनगर	ओरयिंटल	मिरापुर
	बैंक आफ	
	कामर्स	
मुजफ्फरनगर	ओरयिंटल	कैराना
	बैंक आफ	
	कामर्स	
मुजफ्फरनगर	पंजाब	सदर बाजार,
	नैशनल बैंक	मुजफ्फरनगर
आजमगढ़	कैनारा बैंक	आजमगढ़
आजमगढ़	बैंक आफ	आजमगढ़
	इंडिया	

आधारभूत सुविधाओं आदि के लिए व्यवस्थाओं के होने के पश्चात ही शाखाएं खोली जाती हैं।